क्षमता (Capacity) → शिक्षक आमतौर पर स्कूल के नेताओं, शिक्षकों, संकायों और कर्मचारियों की कथित क्षमताओं, कौशल और विशेषज्ञता के सन्दर्भ में शब्द क्षमता का उपयोग करते है- सबसे अधिक जब किसी व्यक्ति या स्कूल की 'क्षमता' का वर्णन करते हैं तो कुछ विशिष्ट को स्कूल - सुधार के प्रयास का नेतृत्व करना या अधिक प्रभावी ढंग से सीखना, यह शब्द अनुकूलन की गुणवत्ता को भी समाहित कर सकता है।

व्यापक रूप से शिक्षा शब्द जाल का थोड़ा उपयोग किया जाता है- शिक्षकों की क्षमताओं कौशल और विशेषज्ञता में सुधार के लिए किए जा रहे किसी भी प्रयास का संदर्भित करता है। यदि उद्देश्य बाहरी सेवाओं पर एक स्कूल की निर्भरता को कम करना है, उदाहरण के लिए शिक्षक कह सकते है कि वे "निर्माण क्षमता का निर्माण" करना चाहते हैं। जब इन शब्दों और वाक्यांशों को स्पष्टता के बिना शिक्षा संदर्भों में उपयोग किया जाता है। तो यह निर्धारित करना मुश्किल हो सकता है। वास्तव में कुछ शैक्षिक पेशेवर, साहित्य और संसाधन स्कूल के नेताओं से एक विशिष्ट क्षेत्र में "क्षमता निर्माण" करने का आह्वान करेंगे। जिसमें कभी भी यह वर्णन किए बिना कि क्षमताओं में क्या सुधार किया जाना चाहिए।

Scanned with CamScanner

नीचे संशोधन
माध्यम
रूप में
में कहा
के रूप
निर्धारित
के सभी
शिक्षा

संशोधन
गया
राज्य
भी बालकों
कार्य के
को
में
धिनियम
2010 से
7 अध्याय
के अन्तर्गत
बच्चों में
नहीं जा
। लाख करोड़
होगी। जिसमें
योग राज्यों

Date
Page

भारत में सामाजिक कार्यक्रम → भारत के केन्द्रीय सरकार के सामाजिक कार्यक्रमों और कल्याण व्यय सरकारी बजट का एक बड़ा हिस्सा है, राज्य और स्थानीय सरकारों के विकास और सामाजिक सुरक्षा नीतियों को लागू करने में भूमिका निभाते हैं। अतिरिक्त कल्याणकारी उपाय प्रणालियाँ भी विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा विशिष्ट रूप से संचालित है। सरकार विशिष्ट पहचान संख्या (आधार) का उपयोग करती है जो भारत में कल्याणकारी उपायों को वितरित करने के लिए प्रत्येक भारतीय के पास है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा → भारत में कई सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य बीमा कम्पनियाँ कार्यरत हैं जो भारतीय मध्यम वर्ग को पूरा करती है। कमजोर भारतीयों के लिए सरकार के पास 'आयुष्मान भारत योजना' है जो एक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम है जिसमें कवरेज है जिसमें 3 दिन पूर्व अस्पताल में भर्ती होना।

Scanned with CamScanner

2002 संविधान के छियासीवें संशोधन अधिनियम शिक्षा के अधिकार के माध्यम से एक मौलिक अधिकार के रूप में पहचाना जाने लगा। लेख 21A में कहा गया है कि 'राज्य राज्य के रूप में इस तरीके से विधि द्वारा निर्धारित करेगा तथा 6-14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा।

संविधान के 86 वें में संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 21(A) जोड़ा गया जो यह प्रावधान करता है कि राज्य विधि बनाकर 6-14 वर्ष के सभी बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य के लिए आबंद करेगा। इस अधिकार को व्यवहारिक रूप देने के लिए संसद में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। इस अधिनियम में 7 अध्याय तथा 38 खण्ड है। इस अधिनियम के अन्तर्गत 6-14 वर्ष के लगभग 22 करोड़ बच्चों में से 92 लाख (4.6%) बच्चे विद्यालय नहीं जा पाते, जिनकी शिक्षा के लिए 1.71 लाख करोड़ रुपये की 5 वर्षों में आवश्यकता होगी। जिसमें से 25 हजार करोड़ रुपये वित्त आयोग राज्यों को देगा।